मानदंडों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है ;

(ख) इनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रक्रिया में आमूलचूल एवं व्यवहारिक परिवर्तन करने का है ;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेतम) (क) और (ख) राहत व्यय वित्त पोषण की विद्यमान योजना 1-4-90 से लागू हुई तथा यह नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।

आयोग ने आपदा राहत निधि के राज्यवार वार्षिक आबंटन की सिफारिश करते समय भारत सरकार द्वारा 10 वर्षों (1980—89) के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंध हेतु स्वीकृत खर्च की उच्चतम सीमा का श्रीमत ध्यान में रखा था।

(ग) से (ङ) दसवां वित्त आयोग राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त अभ्यावेदनों व टिप्पणियों के आधार पर राज्यों को आपदा राहत निधि के आबंटन सहित मान योजना की समीक्षा कर रहा है।

Crop Insurance Scheme

523. SHRI IQBAL SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleasd to state :

(a) what is the number of farmers who have been benefited under the Crop Insurance Scheme during 1992-93 and 1993-94 in the States of Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar ;

(b) whether Government have constituted any high level committee to evaluate this Scheme ; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a The number of farmers benefited under Comprehensive Crop Insurance Scheme (CCIS) during 1992-93 and 1993-94 in Bihar and Madhya Pradesh is as under :

Year	Bihar	Madhya Pradesh
1992-93 . . .	96990	86858
1993-94 . . . (Half yearly)	9306	18099

Punjab, Haryana and Uttar Pradesh States are not implementin the scheme.

(b) and (c) Yes, Sir. A Group under the Chairmanship of, the then Additional Secretary, Deptt. of Agriculture & Cooperation, Shri K. N. Ardhanareeswaran, was constituted to undertake an indepth study and critical review of the functioning of Comprehensive Crop Insurance Scheme, and on the basis of the recommendations of this Group, the following modifications were introduced in CCIS :—

(i) Sum insured was reduced to 100% of crop loan, subject to maximum limit of Rs. 10,000/- per farmer, against the earlier provision of 150% of the loan amount.

(ii) Varying levels of indemnity depending upon variability of yield were introduced.